

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2567 / 2025

सीमा अत्रि

—अपीलार्थी

## बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, चूरु संभाग, चूरु (राज.)।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुनू (राज.)।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.04.2025

आदेश की दिनांक : 01.05.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री कोमल कुमारी गिरी, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Kolinda, अलसीसर, झुंझुनू में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 09.09.1997 को हुई थी और आदेश दिनांक 19.09.2015 के द्वारा व्याख्याता के पद पर पदोन्नति की गई तथा आदेश दिनांक 09.07.2024 के द्वारा उसे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया और पदोन्नति उपरांत उसे आदेश दिनांक 25.01.2025 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Kolinda, अलसीसर, झुंझुनू पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 12.04.2025 के द्वारा काउंसिलिंग करते हुये वर्तमान पदस्थापन स्थान से भामाशी, चूरु पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि वर्तमान विद्यालय में एक पद रिक्त होने के बावजूद अपीलार्थी को स्थानांतरण किया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन विभाग को प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी के स्थानांतरण का परिवर्तन

नहीं किया गया। अपीलार्थी का पति शारीरिक रूप से विकलांग है, जो राजकीय सेवा में जिला झुंझुन में पदस्थापित है और स्थानांतरण नीति के अनुसार यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हैं तो उनका पदस्थापन एक ही स्थान अथवा नजदीकी स्थान पर होना चाहिये, परंतु अपीलार्थी का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण किया गया है, जो उक्त स्थानांतरण नीति के विपरीत एवं विधि विरुद्ध है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2025 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रहने के आदेश फरमाये जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)